GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

1 - 30 Sep., 2019

PIB

PICTURE

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

'वन स्टॉप सॉल्यूशन' का शुभारंभ

PIB, (01 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में देश भर में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के मेगा मिलियन लॉन्च के अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने 1 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters' Service Portal-NVSP) और मतदाता हेल्पलाईन एप (Voter Helpline App) का अनावरण किया।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को बेहतर बनाना है, नागरिकों को बेहतर मतदात सेवाएं प्रदान करना है और आयोग तथा मतदाताओं के बीच संवाद को बेहतर बनाना है।
- 32 सीईओ ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, 700 डीईओ ने जिलों में और लगभग 10 लाख मतदान केंद्रों में बीएलओ/ईआरओ ने देश में सभी स्तरों पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 1 सितंबर, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा।

मुख्य बिंदु

- मतदाता एनवीएसपी पोर्टल (nvsp-in) या मतदाता हेल्प लाइन एप या साझा सेवा केंद्रों या निकट के किसी मतदान सुविधा केन्द्र पर जाकर निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

वर्तमान विवरणों की जांच और सुधार

- निम्न दस्तावेजों के जरिए प्रविष्टियों का सत्यापन/प्रमाणन: (1) भारतीय पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आधार कार्ड (4) राशन कार्ड (5) सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मियों का पहचान पत्र (6) बैंक खाता (7) किसान पहचान कार्ड (8) पेन कार्ड (9) आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड (10) पानी/बिजली/टेलिफोन/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल
- परिवार के सदस्यों का विवरण देना तथा उनकी प्रविष्टियों की जांच
- मतदाता सूची में नाम वाले परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और जो स्थायी रूप से अन्य जगह जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है के विवरणों को अद्यतन करना
- 1 जनवरी, 2001 को या इससे पहले जन्म लिए परिवार के योग्य सदस्यों तथा संभावित मतदाता, जिनका जन्म 2 जनवरी, 2002 से एक जनवरी, 2003 के बीच हुआ है और वे मतदाता के साथ रह रहे हैं के ब्यौरे को जमा करना
- बेहतर मतदात सेवाओं के लिए मोबाइल एप के माध्यम से आवास के जीआईएस को जोड़ना
- वर्तमान के मतदान केंद्र के बारे में अनुभव साझा करना और यदि कोई अन्य वैकल्पिक मतदान केंद्र है तो इसकी जानकारी देना
- ब्यौरे के प्रमाणन से तथा मोबइल नंबर को साझा करने से मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, ईपीआईसी की स्थिति, मतदान दिवस की घोषणाएं, मतदाता स्लिप आदि से संबंधित जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
- मतदाता सूची की क्रमसंख्या में बदलाव, मतदान केंद्र का ब्यौरा बीएलओ/ईआरओ में बदलाव से संबंधित मतदान केंद्र की सभी जानकारी मतदाताओं के साथ साझा की जाएगी।

भारत को चीन से मिला अगले दो वर्षों के लिए सीओपी अध्यक्ष

PIB, (02 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (एमओईएफ और सीसी), श्री प्रकाश जावड़ेकर और मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) के कार्यकारी सचिव, श्रीमान इब्राहिम थिया ने संयुक्त रूप से यूएनसीसीडी के लिए 12 दिन तक चलने वाले 14 वें सम्मेलन (सीओपी14) का उद्घाटन किया।
- पर्यावरण मंत्री जिन्हें अगले दो वर्षों के लिए सीओपी अध्यक्ष भी चुना गया है, ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के प्रभाव को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान खोजने हेतु गहन प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु

- भारत इस वर्ष सीओपी 14 का वैश्विक मेजबान होने के नाते, अगले दो वर्षों यानि 2021 तक के लिए चीन से सीओपी की

अध्यक्षता हासिल कर लेगा।

- भारत को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के सभी तीन रियो सम्मेलनों की सीओपी की मेजबानी करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल होने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है।
- सीओपी 14 की मेजबानी के माध्यम से, भारत वैश्विक स्तर पर भूमि प्रबंधन एजेंडा का संचालन करके अपनी नेतृत्व-क्षमता को उजागर करेगा। यह देश की राष्ट्रीय विकास नीतियों में मुख्यधारा के स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

- सीओपी 14 के प्रमुख परिणाम कृषि, वानिकी, भूमि, जल प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में मौजूदा कार्यक्रमों के बीच अभिसरण और समन्वय प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेंगे, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करेंगे।
- भारत भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने में सक्रिय रहा है। हमने पिछले 5 वर्षों में वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर 15000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर वृक्षरोपण किया है, जो भूमि पुनर्स्थापन में एक बड़ी सफलता है।
- सम्मेलन में 197 दलों के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, वैश्विक व्यापार नेताओं, गैर सरकारी संगठनों, लिंग-आधारित संगठनों, युवा समूहों, पत्रकारों और विश्वास और सामुदायिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

यूएनसीसीडी के बारे में

- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) को 17 जून, 1994 को पेरिस में अपनाया गया और 196 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
- भारत ने 17 दिसंबर 1996 को यूएनसीसीडी सम्मेलन की पुष्टि की। इस सम्मेलन को अन्य दो रियो सम्मेलनों - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) का ष्मातृ सम्मेलनष कहा जा सकता है जो 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक बड़ा निष्कर्ष बनकर उभरा।
- सीओपी 14 का उद्देश्य, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर समिति की चौदहवीं बैठक (सीएसटी 14) और कन्वेंशन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति की अठारहवीं बैठक (सीआरआईसी 18) के साथ भूमि के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है जैसे कि टिकाऊ भूमि प्रबंधन, भूमि क्षरण को रोकना, सूखे का प्रभाव कम करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, रेत और धूल के तूफान से निपटना, लिंग, कार्यकाल के साथ इसका संबंध आदि, और कन्वेंशन को निर्देशित करना क्योंकि राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता है।

''टेराकोटा ग्राइंडर-लॉन्च'

PIB, (02 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वाराणसी की सेवापुरी में पहली बार एक टेराकोटा ग्राइंडर श्लॉन्च किया है। यह मशीन मिट्टी के टूटे-फूटे को बर्तनों को पीस कर पुनरुपयोग के लायक बनाएगी।

मुख्य बिंदु

- पहले मिट्टी के बर्तनों को सामान्य खल-मसल (ओखल और मूसल) में पीसा जाता था और इसके महीन पाउडर को सामान्य मिट्टी में मिला दिया जाता था।

- सामान्य मिट्टी में इस पाउडर को निर्धारित अनुपात में मिलाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों की मजबूती बढ़ जाती है।
- इस अवसर पर, केवीआईसी अध्यक्ष ने ग्रामीणों के बीच 200 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स और अन्य पॉटरी मशीनों का भी वितरण किया।
- इससे न केवल 900 नए रोजगार सृजित होंगे, बल्कि रेलवे मंत्रालय द्वारा जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी निर्देशानुसार वाराणसी रेलवे स्टेशन पर टेराकोटा उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा किया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पे बने, कुल्हड़, गिलास और प्लेट जैसे इको-फ्रेंडली उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

- यह मशीन कुम्हारों के लिए वरदान होगी क्योंकि एमएसएमई केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 400 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ और अन्य टेराकोटा उत्पादों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव रेलवे के तहत विचाराधीन है।

री-प्लान (प्रकृति में प्लास्टिक को कम करना) परियोजना

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत केवीआईसी ने जयपुर में प्लास्टिक मिश्रित कागज का निर्माण प्रारंभ किया है। यह निर्माण कार्य री-प्लान (प्रकृति में प्लास्टिक को कम करना) परियोजना के तहत कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान (केएनएचपीआई) में किया जा रहा है।
- इस परियोजना में, बेकार प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है, साफ किया जाता है, काटा-पीटा जाता है और उसे संशोधित करके मुलायम बनाया जाता है। फिर इसे कागज के कच्चे माल में 80 प्रतिशत (लुगदी) और 20 प्रतिशत प्लास्टिक मिलाया जाता है।
- संस्थान ने सितंबर 2018 से अबतक छह लाख से अधिक हस्तनिर्मित प्लास्टिक मिश्रित कैरी बैग बेचे हैं।

पूर्वालोकन: युद्ध अभ्यास 2019

PIB, (03 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 5 से 18 सितंबर, 2019 तक ज्वाइंट बेस लुईस मैक कॉर्डवाशिंगटन में भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019 आयोजित किया जा रहा है।
- यह भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्ष सहयोग है। दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित किए जाने वाले युद्ध अभ्यास का यह 15वां संस्करण है।

मुख्य बिंदु

- युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सशस्त बलों को ब्रिग्रेड स्तर पर संयुक्त नियोजन के साथ बटालियन स्तर पर एकीकृत रूप से प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। संयुक्त अभ्यास के दौरान विविध कार्रवाइयां की जाएंगी, ताकि एक दूसरे के संगठनात्मक ढांचे और युद्ध प्रक्रियाओं को समझा जा सके।

- इससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन में सहायता मिलेगी और अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सकेगा।
- यह युद्ध अभ्यास एक दूसरे की विशेषज्ञता तथा नियोजन और संचालन क्रियान्वयन के अनुभव को सीखने का आदर्श मंच है।
- दोनों देशों की सैनाएं संयुक्त रूप से प्रशिक्षण नियोजन और क्रियान्वयन का कार्य करेंगी, ताकि विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटा जा सके।
- अंत में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देशों द्वारा संचालन का संयुक्त अभ्यास किया जाएगा।
- दोनों देशों के विशेषज्ञ अकादमिक और सैन्य चर्चा करेंगे ताकि परस्पर हित के विभिनन विषयों पर एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया जा सके।

प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तक यात्रा के दौरान हुए समझौता

PIB, (04 Sep, 2019)

संदर्भ

- "आपसी विश्वास और साझेदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने" के लिए संयुक्त व्यक्तव्य।
- भारत-रूस व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए संयुक्त रणनीति।
- भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच रूसी / सोवियत सेना के उपकरणों के लिए कलपुर्जो का उत्पादन करने संबंधी समझौता।
- भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच मिलकर ऑडियो/विजुअल सह-उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने संबंधी समझौता।

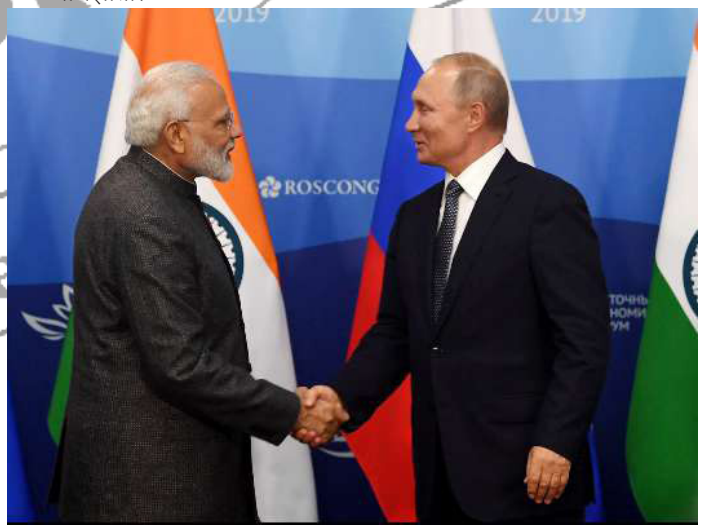

- भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।

- भारत के नौवहन मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच चेन्नई बंदरगाह तथा व्लादिरवोस्तक बंदरगाह के बीच समुद्री संचार के विकास के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा फेडरल कस्टम्स सर्विस (रूसी संघ) के बीच 2019-22 में सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए सहयोग की योजना।
- रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में योजना तैयार करना।
- रूस के सुदूर पूर्व में कोकिंग कोल खनन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सुदूर पूर्व निवेश तथा निर्यात एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
- निवेश सहयोग के लिए निवेश भारत और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के बीच सहयोग का समझौता।
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की) और रॉसकांग्रेस फाउंडेशन के बीच सहयोग का समझौता।
- नई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतिक पहलों के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ और स्वायत्तशासी गैर लाभकारी संगठन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
- एलएनजी के परिशोधन और विपणन एंव एलएनजी आपूर्ति के संयुक्त विकास के सम्बन्ध में सहयोग के बारे में संयुक्त स्टॉक कम्पनी नोवाटेक और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।
- संयुक्त स्टॉक कम्पनी रॉसजियोलॉजिया और स्प्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीच सहयोग का समझौता।

भारत और रूस के बीच 2019-24 के लिए हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग

PIB, (04 Sep, 2019)

संदर्भ

- भारत और रूस के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग का मुद्दा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है और पिछले दो दशकों के दौरान इसमें मजबूती आई है।
- रूस के साथ 2019-24 के लिए हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य निम्नानुसार है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर पुतिन के साथ वार्षिक द्विपक्षीय बैठक के बाद आज रूस के व्लादीवोस्टक में जारी किया गया:-

1. प्राकृतिक गैस क्षेत्र

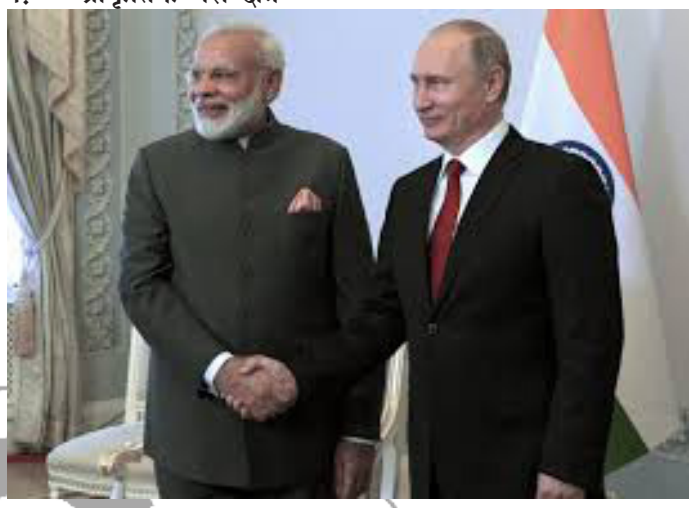

1. दोनों पक्ष भारत के लिए रूस से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं और एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के बदलाव की दिशा में उसके प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में एलएनजी के आयात को मजबूत करने के लिए सहमत हैं।
2. रूस अपने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारत की गैस परियोजनाओं में, विशेषकर भारत में गैस पाइपलाइन नेटवर्क और सिटी गैस वितरण सुविधा के विकास में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा।
3. भारत की निजी और सार्वजनिक कंपनियां आर्कटिक सहित एलएनजी परियोजनाओं में सहयोग की संभावना की तलाश करेंगी। आर्कटिक में सहयोग के बारे में, भारतीय कंपनियां जेएससी नोवाटेक की एलएनजी आर्कटिक परियोजनाओं सहित, रूसी कंपनियों के साथ निकट सहयोग कायम करने की संभावना का परीक्षण करेंगी।
4. दोनों पक्ष भारत के लिए एलएनजी की आपूर्ति को बढ़ाने और भारत में गैस बाजार के संयुक्त विकास का स्वागत करते हैं।

2. हाइड्रोकार्बन खोज क्षेत्र

1. दोनों पक्ष रूस और भारत की अग्रणी तेल एवं गैस कंपनियों के बीच रूस, भारत और तीसरे देशों के खोज क्षेत्र में सफल सहयोग का स्वागत करते हैं।
2. दोनों पक्ष रूस में तेल एवं गैस संसाधनों में भारतीय निवेशों की अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हैं।

GS World Committed To Excellence

भारत रूस में तेल एवं गैस के उत्पादन में और अधिक निवेश के अवसरों के प्रति आशान्वित है।

3. दोनों पक्ष हाइड्रोकार्बन खोज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और इसके बारे में अग्रणी कंपनियों के बीच वार्ता जारी रखेंगे।

3. परिशोधन और विपणन क्षेत्र

1. भारत के तेल परिशोधन क्षेत्र में रूस का निवेश एक स्वागत-योग्य कदम रहा है। भारत की ओर से भारत के तेल परिशोधन, पेट्रोकेमिकल और संबंधित क्षेत्रों में रूस की सार्वजनिक और निजी कंपनियों को और अधिक निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
2. दोनों पक्ष इस क्षेत्र में सहयोग की नई परियोजनाओं की पहचान के लिए काम करेंगे।

- दोनों पक्ष भारतीय तेल परिशोधन इकाइयों के लिए कच्चे और ईंधन तेल की आपूर्ति के लिए परस्पर लाभदायक चौनलों की स्थापना के बारे में समझौते कायम करने के लिए प्रयास करेंगे।

4. प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, तीसरे देश का सहयोग

1. दोनों पक्ष उभरती प्रौद्योगिकियों सहित ऊर्जा क्षेत्र में ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त अनुसंधान के नये तरीके विकसित करने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के आदान-प्रदान को सशक्त और विविधतापूर्ण बनाएंगे।
2. दोनों पक्ष ऊर्जा क्षेत्र में तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं को हाथ में लेने की संभावना तलाशने के लिए सहमत हैं।''

छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता

PIB, (06 Sep, 2019)

संदर्भ

- छठी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) 7-9 सितंबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
- इस वार्ता के अंतर्गत ढांचागत संरचना, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण, औषधि तथा नीति समन्वय पर संयुक्त कार्यकारी समूहों (जेडब्ल्यूजी) की गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएगी।
- इसके बाद प्रौद्योगिकी स्थलों का दौरा किया जाएगा तथा जी-2 जी बैठकें होंगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के चौयरमेन तथा चीनी पक्ष का नेतृत्व एनडीआरसी के चौयरमेन करेंगे।
- दोनों पक्षों के नीति-निर्माता तथा उद्योग एवं शिक्षा जगत के प्रतिनिधि इस वार्ता में भाग लेंगे।

संरचना

- भारतीय पक्ष की तरफ से नीति आयोग और चीनी पक्ष की ओर से नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफोर्म्स कमीशन (एनडीआरसी) एसईडी व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। इसके तहत प्रति वर्ष एक वार्षिक वार्ता का आयोजन क्रमशः दोनों देश की राजधानियों में किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- एसईडी का गठन दिसंबर, 2010 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। द्विपक्षीय सहयोग के प्रभावी व्यवस्था के रूप में एसईडी योगदान दे रहा है।
- एसईडी वार्ता के तहत दोनों पक्ष सर्वोत्तम अभ्यासों तथा क्षेत्र विशेष पर आधारित चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करते हैं।

5वीं एसईडी

- 5वीं एसईडी का आयोजन 14 अप्रैल, 2018 को बीजिंग में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के वाइस चौयरमेन डॉ. राजीव कुमार ने किया था।
- इस वार्ता के दौरान संयुक्त कार्य समूहों की प्रगति तथा परस्पस्पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था।

28वां इंडो-थाई कॉरपेट

PIB, (06 Sep, 2019)

संदर्भ

- भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना के बीच 5 से 15 सितंबर, 2019 तक 28वां भारत-थाईलैंड की समन्वयन गश्त (इंडो-थाई कॉरपेट) का आयोजन किया जाएगा।
- कॉरपेट में भारतीय नौसेना पोत केसरी और थाईलैंड की शाही नौसेना पोत क्राबुरी भाग लेंगे। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती हवाई जहाज भी शामिल होंगे।

मुख्य बिंदु

- अंडमान-निकोबार कमान के भारतीय नौसेना के पोत और हवाई जहाज वर्ष 2003 से थाईलैंड की शाही नौसेना के साथ दो वर्ष

में एक बार कॉरपेट में हिस्सा लेते रहे हैं।

- इंडो-थाई कॉरपेट का मकसद संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानून समझौते का कारगर क्रियान्वयन है।
- इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों/ मादक पदार्थों की तस्करी/समुद्री डाकुओं की गतिविधियों को रोकना, तस्करी, गैर-कानूनी अप्रवासन की रोकथाम तथा समुद्र में तलाशी और बचाव गतिविधियां चलाना शामिल हैं।
- 28वें इंडो-थाई कॉरपेट से भारत और थाईलैंड के बीच रिश्ते मजबूत होंगे और समुद्री सहयोग बढ़ेगा। क्षेत्र में बेहतर समुद्री शांति व्यवस्था के जरिए हिंद महासागर को शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में प्रगति होगी।

भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर डीग्रेडेड भूमि को ठीक करेगा भारत

PIB, (09 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 14वें मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कॉप-14) की उच्चस्तरीय बैठक का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रियो सम्मेलन के सभी तीन प्रमुख विषयों को समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
- प्रधानमंत्री ने कहा, 'आगे कदम बढ़ाते हुए भारत को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण के मुद्दों को हल करने में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए पहलों का प्रस्ताव करने में खुशी होगी।'

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री ने घोषणा की, 'भारत अब से 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर से 26 मिलियन हेक्टेयर तक की डीग्रेडेड भूमि को ठीक करने की महत्वाकांक्षा रखता है।'
- इसके मद्देनजर अत्यंत डीग्रेडेड भूमि के 26 मिलियन हेक्टेयर रकबे की भूमि उत्पादकता तथा जैव प्रणाली को बहाल करने पर ध्यान दिया जाएगा।

- इसके तहत डीग्रेडेड कृषि योग्य, वन और अन्य परती जमीनों को केन्द्र में रखा जाएगा।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि क्षरण नियंत्रण लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम के संबंध में यूएनसीसीडी के सदस्य देशों के क्षमता निर्माण तथा समर्थन के लिए एक वैश्विक तकनीकी समर्थन संस्थान बनाने के भारतीय प्रस्ताव की घोषणा की।
- पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कॉप-14 पर्यावरण संबंधी अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए एक विश्व मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, 'विश्व भर के 190 से अधिक देश, 100 मंत्री और 8000 भागीदार यूएनसीसीडी कॉप-14 में भूमि बहाली और जलवायु के संवर्धन पर चर्चा करने तथा इस दिशा में काम करने के लिए एकजुट हुए हैं।'
- जलापूर्ति बढ़ाना, जल की पुनःपूर्ति करना, जल अपव्यय को कम करना और मिट्टी की नमी को कायम रखना, भूमि तथा जल रणनीति का अह्म हिस्सा है।'

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'आंगन- की शुरुआत

PIB, (09 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में 09 सितंबर, 2019 को भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 'आंगन' की शुरुआत नई दिल्ली में की गई।
- भारत-जर्मनी तकनीकी सहयोग के तहत GIZ (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये सोसाइटी- Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit) की सहायता से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency-BEE) ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है।
- इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ आदि भाग ले रहे हैं।
- भाग ले रहे विशेषज्ञ व्यावसायिक और आवासीय भवनों के डिजाइन तथा निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष विकल्पों एवं

प्रौद्योगिकियों के विषय पर विचार-विमर्श करेंगे।

- एक अनुमान के मुताबिक, भवन ऊर्जा दक्षता गतिविधियों में 2000 बिलियन रुपए के निवेश से 388 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हो सकती है।
- यह सम्मेलन संसाधनों की दक्षता पर विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा।

पृष्ठभूमि

- उपभोक्ताओं को उचित और किफायती दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता आवश्यक है।
- आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, ऊर्जा दक्ष उपकरण आदि को लेकर जागरूकता की कमी के कारण इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता औसत रही है।
- सम्मेलन के दौरान ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्त्ताओं, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्त्ताओं, अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।

मोतिहारी-अमलेखगंज (नेपाल) पाइपलाइन

PIB, (10 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली ने दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- यह पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है।

- इस अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर प्रशंसा व्यक्त की। यह परियोजना निर्धारित समयसीमा से काफी पहले पूरी हो गई है।

मुख्य बिंदु

- 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी।
- इस पाइपलाइन की क्षमता दो मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। उन्होंने प्रधानमंत्री ओली की उस घोषणा का स्वागत किया, जिसमें नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की बात कही गई है।
- उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों का प्रगाढ़ होना जारी रहेगा तथा इनका अलग-अलग क्षेत्रों तक विस्तार होगा।

भारत का सबसे ऊँचा हवाई यातायात नियंत्रण टॉवर

PIB, (11 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर नवनिर्मित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टावर का केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने औपचारिक उद्घाटन किया।
- इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एटीसी टावर में विश्व की सबसे बेहतर तकनीक स्थापित की गई।
- नई तकनीकी के प्रयोग से पहले से ज्यादा दक्षता से हवाई यातायात का संचालन होगा।
- इसका संचालन करने वाले हवाई नियंत्रक भी विशेष तौर से प्रशिक्षित हैं। इन दोनों के मेल से हवाई यातायात पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा।

- आने वाले समय में नागरिक उड्डयन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व ऊंचाई तक ले जाएगा।

मुख्य बिंदु

- एटीसी के नए टावर परिसर में प्रमुख रूप से तीन इमारतें शामिल हैं। इनमें एयरोड्रम कंट्रोल टॉवर, एरिया और एप्रोच कंट्रोल सर्विसेज बिल्डिंग प्रमुख हैं।
- इसके निर्माण पर 250 करोड़ रुपये की लागत आई है, जबकि उपकरण लगाए जाने पर 100 करोड़ खर्च किए गए हैं।
- नए एटीसी टावर और उन्नत तकनीक से आइजीआइ एयरपोर्ट पर हवाई यातायात संचालन की सुरक्षा और क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। यहां आधुनिक एयर नेवीगेशन सिस्टम और उन्नत एटीसी स्वचालन प्रणाली लगाई गई है।
- नवनिर्मित एटीसी टॉवर देश में सबसे ऊंचा और दुनिया में सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। यहां से हवाई यातायात नियंत्रक एयरपोर्ट के रनवे, टैक्सी-वे और पार्किंग स्टैंड सहित तमाम परिचालन क्षेत्र पर हो रही गतिविधियां देख सकेंगे। इससे वे त्वरित निर्णय लेने के साथ ही दुर्घटनाओं को समय रहते रोक सकेंगे।

स्वच्छता ही सेवा-2019 अभियान

PIB, (11 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने मथुरा में स्वच्छता पर एक व्यापक देशव्यापी जागरूकता अभियान - स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2019 का शुभारंभ किया।
- स्वच्छता ही सेवा-2019 के तहत 'प्लास्टिक कचरा जागरूकता और प्रबंधन' पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसे 11 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाना है।
- केन्द्र सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन और पेयजल एवं स्वच्छता विभागों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एसएचएस के शुभारंभ का आयोजन किया गया था।
- प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये गये भाषण में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया गया था।
- इस वर्ष की स्वच्छता ही सेवा का विषय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कार्य-योजना

- डीपीआईआईटी सीमेंट भट्टों में 2 अक्टूबर, 2019 को एकत्र प्लास्टिक अपशिष्ट की रि-साइक्लिंग सुनिश्चित करेगा और 2 अक्टूबर, 2019 को ही राष्ट्रव्यापी श्रमदान के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र करेगा।

- डीपीआईआईटी ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपने यहां सभी औद्योगिकी एस्टेट्स, पार्कों, कारिडोरों और औद्योगिक क्षेत्रों से 11 सितम्बर, 2019 से शुरू होने वाले स्वच्छ्ता ही सेवा 2019 के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र करने का अनुरोध किया है।
- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने डीपीआईआईटी से सीमेंट भट्टों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को जरूरी बनाने का अनुरोध किया है।
- डीपीआईआईटी यह सुनिश्चित करेगा कि इस वर्ष दिवाली तक सीमेंट भट्टों में एकत्र किया गया प्लास्टिक 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए डीपीआईआईटी के कर्मचारी श्रमदान करेंगे और पूरे देश में प्रौद्योगिक क्षेत्रों और उनके आस-पास प्लास्टिक कचरे का संग्रह सुनिश्चित करेंगे।

स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण

PIB, (11 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने देश में ही विकसित कम वजनी, दागो और भूल जाओ की तकनीक वाली मैन पोर्टेबल (मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली) एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एमपीएटीजीएम का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफल परीक्षण किया।
- मिसाइल को एक मैन पोर्टेबल ट्राइपॉड से दागा गया और इसके निशाने पर एक नकली सक्रिय टैंक था।
- मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में लक्ष्य को निशाना बनाया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस दौरान मिशन के सभी उद्देश्य हासिल किए गए।

मुख्य बिंदु

- यह एमपीएटीजीएम का तीसरा सफल परीक्षण है। यह उन्नत

उड़ा खूबियों के साथ मिसाइल अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से लैस है।

- इस परीक्षण ने सेना के लिए तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी मैन पोर्टबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल हासिल करने का रास्ता बना दिया है।
- मिसाइल का वजन लगभग 14 किलोग्राम है और इसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ पैदल सेना की बटालियनों द्वारा किया जा सकता है।
- इसके पास लगभग 2.5 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है और यह सोवियत-युग के एंटी-टैंक मिसाइलों की जगह लेगा जिनका उपयोग सेना द्वारा किया जा रहा है।
- संभावना जताइ जा रही है कि इन मिसाइलों का 2021 से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

PIB, (12 Sep, 2019)

संदर्भ

- किसानों का जीवन सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का शुभारंभ किया।
- इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा।
- प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना भी शुरू की है।
- इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी।
- इस योजना से लगभग 3 करोड़ छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे।
- यह योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है।
- पति और पत्नी इस योजना का लाभ अलग-अलग भी उठा सकते हैं।
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

कौन और कैसे ले सकता है योजना का लाभ

- किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसानों के लिए हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है।

- इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है। 60 साल होने के बाद उन्हें 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलने लगेगी।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

- नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।
- वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है।
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।
- योजना से बाहर निकलना तथा वापसी
- यदि लाभार्थी कम-से-कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।
- यदि नियमित भुगतान में विलंब होता है या अल्प समय के लिये भुगतान रूक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाए का भुगतान कर सकते हैं।

व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

PIB, (12 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने रांची, झारखंड में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है।
- यह पेंशन योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों तथा स्वरोजगार में

लगे व्यक्तियों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

- इस योजना के अंतर्गत भावी लाभार्थियों के लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।
- इस योजना के तहत व्यापारी अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोग www-maandhan-in/vyapari पोर्टल पर जाकर भी खुद नामांकन कर सकते हैं।

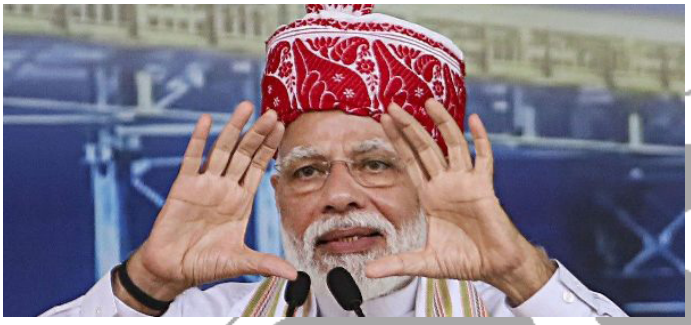

नामांकन प्रक्रिया: मुख्य विवरण

- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 40 लाख से अधिक वार्षिक व्यापार वाले व्यापारियों के लिए जीएसटीआईएन की जरूरत है।
- योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नामांकन नि:शुल्क है. नामांकन स्व-प्रमाणन पर आधारित है।

क्या है?

- केंद्र सरकार ने दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के अहम योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है।
- यह 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।
- इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है।
- लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार)/ पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50 प्रतिशत योगदान होगा और शेष 50 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत मासिक योगदान को कम रखा गया है। लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान देना होगा।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के अहम योगदान को देखते हुए व्यापारियों तथा स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है।
- यह पेंशन योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
- इस योजना में साल 2019-20 तक 25 लाख लाभार्थियों तथा साल 2023-2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से देश के करीब तीन करोड़ व्यापारियों के फायदा होने की उम्मीद है।

भारत ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब में शामिल

PIB, (12 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में भारत एक नए सदस्य के रूप में ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एएमआरआरएंडडी, AMRR-D) हब में शामिल हो गया है। इसकी घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली में की।
- इससे एएमआरआरएंडडी में चुनौतियों का सामना करने और 16 देशों, यूरोपीय आयोग, 2 परोपकारी प्रतिष्ठानों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (पर्यवेक्षकों के रूप में) में सहयोग और समन्वय में सुधार लाने के लिए वैश्विक भागीदारी का विस्तार हुआ है।

AMRR-D हब क्या है?

- जी-20 नेताओं द्वारा 2017 में किए गए आह्वान के कारण विश्व स्वास्थ्य एसेंबली के 71वें सत्र से इतर इस केंद्र की शुरूआत मई, 2018 में की गई थी।

- ग्लोबल एएमआरआरएंडडी हब का परिचालन बर्लिन स्थित सचिवालय से हो रहा है।
- वर्तमान में इसे जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (बीएमबीएफ) और संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय (बीएमजी) से प्राप्त अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- इस वर्ष से भारत इसका सदस्य होगा।

विश्व स्वास्थ्य सभा

- विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है।

- इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किये गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्यों में संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम के बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना शामिल है।
- प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जाता है।

लाभ

- ग्लोबल एएमआरआरएंडडी हब की भागीदारी से भारत सभी भागीदारों देशों की मौजूदा क्षमताओं और संसाधनों और सामूहिक रूप से ने अनुसंधान और विकास हस्तक्षेपों के बारे में ध्यान केंद्रित करते हुए भरपूर लाभ उठाएगा और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने में सक्षम होगा।

भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-2019

PIB, (12 Sep, 2019)

संदर्भ

- भारत और थाइलैंड के बीच मैत्री-2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 16 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2019 तक मेघालय के उमरोई में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जाएगा।
- दोनों देशों ने पिछले एक महीने में इस तरह के दो सैन्य अभ्यास किए हैं।
- इस अभ्यास में भारत और थाइलैंड की सेनाओं के हरेक 50-50 सैनिक हिस्सा लेंगे।
- इसका मुख्य उद्देश्य अपने-अपने देशों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों को साझा करना है।

मुख्य बिंदु

- अभ्यास मैत्री एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- इसे साल 2006 से थाइलैंड और भारत में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- इस अभ्यास में संयुक्त प्रशिक्षण, दोनों देशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों एवं उपकरणों से परिचय शामिल है।
- इस अभ्यास में जंगली और शहरी परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी कार्यवाही पर आधारित कंपनी स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है।
- सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों का संचालन भारत अनेक देशों के साथ करता है। लेकिन, वैश्विक आतंकवाद के बदलते परिदृश्य में, थाइलैंड के साथ अभ्यास मैत्री दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए अत्यधिक अहम है।

- संयुक्त सैन्य अभ्यास से भारतीय सेना तथा रॉयल थाइलैंड आर्मी के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा।
- इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
- इस अभ्यास में घेराबंदी और खोज, छापेमारी एवं खोजो और नष्ट करो मिशनों जैसे अभियानों के अतिरिक्त शहरी माहौल में क्षेत्र प्रभुत्व अभियानों के संचालन के तौरख़ तरीके साझा किये जायेंगे।

भारत-थाईलैंड संबंध

- भारत के थाईलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो कई सदियों पहले स्थापित किये गये थे. दोनों देशों ने साल 1947 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किये थे।
- दोनों देशों द्वारा जनवरी 2012 में रक्षा सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ, भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा संबंध सालों से बेहतर होते रहे हैं।
- दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में मार्च 2019 में आयोजित वार्षिक उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता, 7वां संस्करण के माध्यम से रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है।
- भारत के नौसेना कई मोर्चों पर रॉयल थाई नेवी के साथ सहयोग करती है। इसमें परिचानात्मक बातचीत, प्रशिक्षण विनिमय तथा हाइड्रोग्राफिक सहयोग शामिल हैं।

इस्पात आयात निगरानी प्रणाली लॉन्च

PIB, (16 Sep, 2019)

संदर्भ

- हल ही में वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (सिम्स) लॉन्च की।
- यह प्रणाली संयुक्त राज्य इस्पात आयात निगरानी और विश्लेषण (सीमा) प्रणाली के अनुरूप इस्पात मंत्रालय के परामर्श से विकसित की गई है।
- सिम्स सरकार और इस्पात उद्योग (उत्पादक) और इस्पात उपभोक्ता

GS World Committed To Excellence

(आयातक) सहित हितधारकों को इस्पात आयातों के बारे में अग्रिम सूचना देगा, ताकि कारगर नीतिगत दखल दिया जा सके।

मुख्य बिंदु

- इस प्रणाली के तहत विशेष इस्पात उत्पादों के आयातकों को सिम्स के वेबपोर्टल पर आवश्यक सूचना देते हुए अग्रिम रूप से पंजीकरण कराना होगा।
- यह पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। आयातित माल के आगमन की संभावित तारीख के पहले आयातक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह पंजीकरण माल आगमन के 60वें दिन से पहले और 15वें दिन के बाद नहीं किया जाना चाहिए। स्वचालित आधार पर प्राप्त होने वाली पंजीकरण संख्या 75 दिन की अवधि तक मान्य रहेगी।
- सिम्स पर आयातकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली इस्पात आयात सूचना की निगरानी इस्पात मंत्रालय करेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस्पात आयात निगरानी प्रणाली को 5 सितंबर, 2019 को अधिसूचना संख्या 17 के जरिये अधिसूचित किया गया है। इसे 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी बनाया गया है।

विश्व ओजोन दिवस

PIB, (16 Sep, 2019)

संदर्भ

- हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य दुनियाभर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकार अल्ट्रा वाइलट किरणों से बचाने और हमारे जीवन को संरक्षित रखनेवाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है।
- यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि यह वियना संधि के तहत ओजोन परत के संरक्षण के लिए सभी देशों के द्वारा लिया गया एक प्रण है ताकि पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखा जा सके।
- इस साल यानी विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम '32 years and Healing' है।
- इस थीम के जरिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुनियाभर के देशों द्वारा ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु की रक्षा के लिए तीन दशकों से किए जा रहे प्रयासों को सिलेब्रेट किया जाएगा।

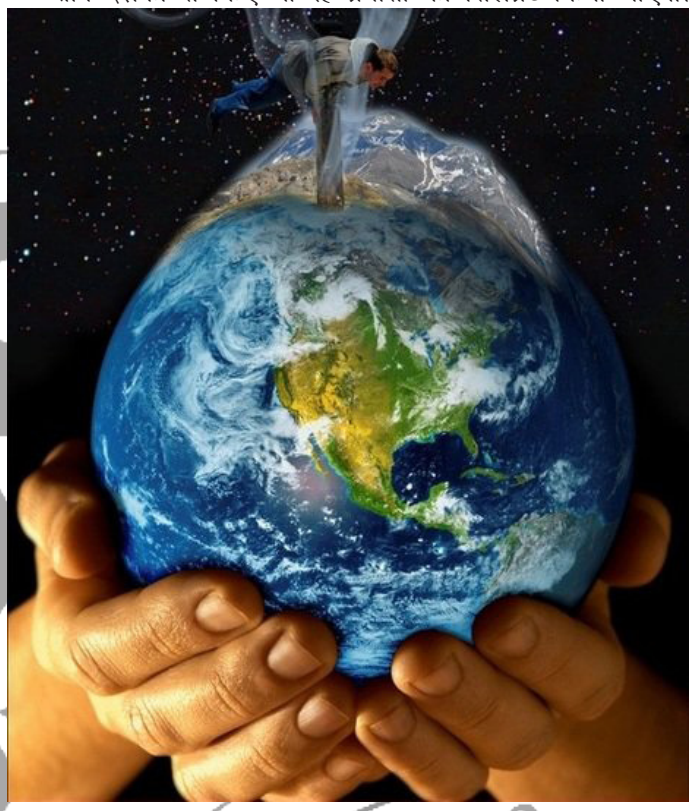

कूलिंग एक्शन प्लान

- भारत मार्च, 2019 में समग्र 'कूलिंग एक्शन प्लान' शुरू करने वाले देशों में शामिल हो गया है।
- इसके तहत आवासीय और व्यापारिक इमारतों, कोल्ड-चेन, रेफ्रीजिरेशन, यातायात और उद्योगों के लिए परिशीतन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
- 'कूलिंग एक्शन प्लान' के अंतर्गत परिशीतन की मांग में कटौती करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री अंतोनियो गुटारेस ने भारत के 'कूलिंग एक्शन प्लान' की सराहना करते हुए कहा है कि सभी देशों को इसी तरह की योजना का विकास करना चाहिए।

उद्देश्य

- उल्लेखनीय है कि भारत के 'कूलिंग एक्शन प्लान' का उद्देश्य है (1) सभी क्षेत्रों में 2037-38 तक कूलिंग की मांग में 20 से 25

प्रतिशत कटौती करना, (2) वर्ष 2037-38 तक रेफ्रीजिरेशन की मांग में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी, (3) वर्ष 2037-38 तक कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40 प्रतिशत तक कम करना, (4) कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों को अनुसंधान के लिए मान्य करना (5) वर्ष 2022-23 स्किल इंडिया मिशन के साथ सेवा क्षेत्र के 1,00,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना है।

ओजोन गैस क्या है?

- ओजोन एक वायुमण्डलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। तीन ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने से ओजोन (O3) का एक अणु बनता है।
- इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे तीव्र गंध आती है.
- ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैगनी किरणों से हम सभी लोगों की रक्षा करती है।
- ओजोन परत का निर्माण ऑक्सिजन के तीन एटम से मिलकर होता है। यह बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और इसे O3 के जरिए प्रजेंट किया जाता है।
- इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से भी होता है और ह्यूमन ऐक्टिविटीज़ से भी।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर, 1987 को विभिन्न देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन 1 जनवरी, 1989 को हुआ था।
- ऐसा विश्वास किया जाता है की वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जायेगा।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल पर वार्ता करने और सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर की तिथि को लोग एकत्रित होते हैं। इस वार्ता में चर्चा का प्रमुख विषय ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थ होते हैं।
- यह वार्ता वस्तुत: ओजोन परत के सन्दर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमे ओजोन परत को नुकसान पहुँचले वाले पदार्थो को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही देशो से इसके उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने का संकल्प लिया जाता है।

'वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर

PIB, (16 Sep, 2019)

संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स स्टडीज एंड एनालिसिस (आईएसएसए) दिल्ली ने मेरीटाइम वॉरफेयर सेंटर, विशाखापत्तनम के सहयोग से नई पीढ़ी का 'वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर' तैयार किया है ताकि भारतीय नेवी की समकालीन संचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- इस सॉफ्टवेयर के जरिये मेरीटाइम वॉरफेयर सेंटरों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्य कंप्यूटर उपकरणों के जरिये प्रशिक्षण देने में सहायता होगी।

उद्देश्य

- इस वॉर गेम साफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य युद्ध का माहौल बना कर नौसेना को युद्ध अभ्यास कराना है, जिससे समुद्री वॉरफेयर सेंटर को नवीनतम तकनीक और कम्प्यूटिंग टूल का इस्तेमाल करने का मौका मिले सके।
- इस सेंटर में कई सेनाओं को शामिल कर विश्व स्तर पर खेले जाने वाले वारगेमिंग दृश्य का माहौल पैदा किया जाएगा है।
- यह वॉर गेम वाइड एरिया नेटवर्क के जरिये भौगोलिक तौर पर फैले इलाके में युद्ध अभ्यास करने में सहायक होगा। इस वारगेम का नौसैनिक रणनीतिज्ञ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

एसयू-30 एमकेआई से हवा से-हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र का सफल परीक्षण

PIB, (17 Sep, 2019)

संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से किया गया था।
- इस मिसाइल ने पश्चिम बंगाल में एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी

थी। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिसा के तट पर किया गया है। यह मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने निशाने पर सटीक वार किया। अस्त्र मिसाइल पूरी तरह से देश में बनी है।

अस्त्र मिसाइल के बारे में

- अस्त्र मिसाइल श्बीवीआरश्(बियोंड विजुअल रेंज) हवा से हवा मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है।
- यह एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी मौसम में उपयोग की जा सकती है। इस मिसाइल को एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है।
- इस मिसाइल को डीआरडीओ ने मिराज-2000 एच, मिग-29, मिग-29के, एलसीए तेजस, मिग-21 बायसन और सुखोई एसयू-30 एमकेआई विमानों में लगाने हेतु विकसित किया है।
- इस मिसाइल में ठोस ईंधन प्रणोदक का उपयोग किया गया है। सुपर सोनिक गति से यह मिसाइल हवा में उड़ रहे किसी भी भी लक्ष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है।
- यह मिसाइल अपनी श्रेणी की हथियार प्रणालियों में सबसे अच्छा है। इस मिसाइल के अभी तक कई परीक्षण किए जा चुके हैं।
- यह मिसाइल दुश्मन विमानों को 70 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने की क्षमता रखती है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019

PIB, (18 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैटरी-युक्त उपकरण है, जो निकोटिन वाले घोल को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है।
- एयरोसोल, सामान्य सिगरेटों में एक व्यसनकारी पदार्थ है। इनमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम, जलाने नहीं, गर्म होने वाले (हिट नॉट बर्न) उत्पाद, ई-हुक्का और इस प्रकार के अन्य उपकरण शामिल हैं।
- ऐसे नए उत्पाद आकर्षक रूपों तथा विविध सुगंधों से युक्त होते हैं तथा इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा है। विकसित देशों में विशेषकर युवाओं और बच्चों में इसने एक महामारी का रूप ले लिया है।

कार्यान्वयन

- अध्यादेश की घोषणा के बाद, ई-सिगरेटों का किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित), वितरण अथवा विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन सहित) एक संज्ञेय अपराध माना जायेगा और पहली बार अपराध के मामले में एक वर्ष तक कैद अथवा एक लाख रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों; और अगले अपराध के लिए तीन वर्ष तक कैद और पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण के लिए भी छह माह तक कैद अथवा 50 हजार रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
- अध्यादेश लागू होने की तिथि पर, ई-सिगरेटों के मौजूदा भंडारों के मालिकों को इन भंडारों की स्वत: घोषणा करके, निकटवर्ती पुलिस थाने में जमा कराना होगा।
- पुलिस उप निरीक्षक को अध्यादेश के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया है।
- अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए, केंद्र अथवा राज्य सरकार किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को अधिकृत अधिकारी के रूप में निर्धारित कर सकती है।

मुख्य प्रभाव

- ई-सिगरेटों के निषेध के निर्णय से लोगों को, विशेषकर युवाओं और बच्चों को ई-सिगरेटों के व्यसन के जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी।

- अध्यादेश के लागू होने से सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को बल मिलेगा और तंबाकू के इस्तेमाल में कमी लाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे जुड़े आर्थिक बोझ और बीमारियों में भी कमी आएगी।

पृष्ठभूमि

- ई-सिगरेटों को प्रतिबंधित करने पर विचार करने के लिए, सरकार द्वारा 2018 में सभी राज्यों के लिए जारी की गई एक चेतावनी की पृष्ठभूमि में मौजूदा निर्णय लिया गया है।
- पहले ही 16 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने अपने क्षेत्राधिकारों में ई-सिगरेटों को प्रतिबंधित किया है।
- ध्यान रहे कि इस विषय पर हाल में जारी एक श्वेत-पत्र में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भी फिलहाल उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर ई-सिगरेटों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सदस्य देशों से मांग की है कि इन उत्पादों को प्रतिबंधित करने सहित समुचित उपाय किए जाएं।
- लोगों के लिए तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने में मद्दगार माने जाने वाले परीक्षित निकोटिन और गैर-निकोटिन फार्माकोथेरेपियों से पृथक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निवारण उपकरणों के रूप में ई-सिगरेटों की अनुमति नहीं दी है।
- निकोटिन के अलावा, अन्य साइकोएक्टिव पदार्थों के वितरण के लिए भी ई-सिगरेटों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ई-सिगरेटों से जुड़े जोखिमों के बिना, वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित निकोटिन के लिए प्रतिस्थापन थेरेपियां, तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए च्विंगमों, खट्टी-मीठी गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं।
- ई-सिगरेटों और ऐसे उपकरणों के व्यापक इस्तेमाल और अनियंत्रित फैलाव से, तंबाकू इस्तेमाल में कमी लाने के सरकार के प्रयास निष्प्रभावी सिद्ध होंगे।

तीन देशों की नौसेनाओं का समुद्री युद्धाभ्यास शुरू

PIB, (19 Sep, 2019)

संदर्भ

- अंडमान के समुद्र में 18 सितंबर, 2019 से भारतीय नौसेना, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (आरएसएन) और रॉयल थाई नेवी (आरटीएन) के बीच एसआईटीएमईएक्स-19 (सिंगापुर, भारत और थाईलैंड समुद्री युद्धाभ्यास) शुरू हो गया है।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत रणवीर, मिसाइल जंगी पोत सुमेधा, एक तटीय पेट्रोल पोत और लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी8आई संयुक्त रूप से दुर्जेय श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ पोत आरएसएस टेनासियस गाइडेड मिसाइल पोत एचटीएमएस क्राबुरी के साथ शामिल है।

मुख्य बिंदु

- इस अभ्यास में नौसेनाओं के बीच समुद्री सक्रियता बढ़ाने के लिए हवाई सुरक्षा एवं संचार अभ्यासों और बल सुरक्षा उपाय पर ध्यान दिया गया है।
- सर्वोत्तम तौर तरीकों के अनुभव साझा करने के लिए अभ्यास में शामिल पोतों के बीच समुद्री राइडर्स का आदान-प्रदान किया गया।
- इससे पहले, पोर्ट ब्लेयर में एसआईटीएमईएक्स-19 के बंदरगाह चरण का समापन हुआ। इसमें विषय विशेषज्ञ एक्सचेंज (एसएमईई) के रूप में हुई पेशेवर बातचीत, जल यात्रा से पहले कांफ्रेंस शामिल है।
- इनमें कमांड टीमों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे पोतों की संयुक्त टीमों के बीच दोस्ताना बॉस्केटबाल मैच भी खेला गया।
- प्रत्येक प्रतिभागी देश के व्यंजनों को दिखाने के लिए बंदरगाह चरण के दौरान एक फूड फेस्टीवल का भी आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन - रबी अभियान 2019

PIB, (20 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में 20 सितंबर, 2019 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी अभियान-2019 के लिये राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने खाद्यान्नों के अभूतपूर्व उत्पादन (285 मिलियन टन) के बारे में चर्चा की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कारगर रूप से लागू करने के लिये राज्य सरकारों की सराहना की।
- राज्य सरकारों के इस सहयोग से ही चावल (116 मिलियन टन), गेहूं (102.5 मिलियन टन), दलहनों और तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन संभव हुआ है।
- हालाँकि तिलहनों की कमी एक चिंताजनक बिंदु है, खाद्य तेलों

की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और आयात में कमी लाने के लिये एक अलग अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।

- जिला स्तर पर किसान संगठनों से परामर्श के बाद उर्वरकों की मांग की जानी चाहिये। साथ ही राज्य के कृषि विभागों को समय रहते केंद्र सरकार को उर्वरक की अपनी मांगों से अवगत कराना चाहिये, जिससे फसलों के महत्त्वपूर्ण चरणों में किसानों के लिये उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
- कृषि विभाग ने राज्यों के कृषि विभागों की सक्रिय भागीदारी से रबी फसलों, दलहनों और तिलहनों के लिये बीज के मिनी किट वितरित करने का निर्णय लिया है।
- जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड का सरोकार है, बड़ी संख्या में किसानों को इसमें शामिल करने के लिये पंजीकरण शुल्क में छूट देने, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए न्यूनतम समय, ऋणों की संख्या बढ़ाने जैसे अनेक बदलाव किये गए हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए राज्यों के कृषि विभागों से विवरण प्राप्त किये गए हैं और तदनुसार योजना की समीक्षा की जाएगी।
- रबी तिलहनों और दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त तिलहन और दलहन की 45 जैव बायोफोर्टिफिकेशन किस्में जारी की गई हैं। इनमें प्रोटीन और पोषक तत्वों आदि की काफी मात्रा मौजूद है।

किये जाने वाले उपाय:-

- इसके लिये आवश्यक है कि किसानों को सर्वाधिक लाभ मुहैया कराने के लिये खेती को कृषि प्रयोगशालाओं से सीधे जोड़ा जाए।
- उर्वरकों की जरूरतों की जानकारी जिला स्तर पर मुहैया कराई जाए तथा इसे बाद में संबंधित राज्य सरकारों के कृषि विभाग द्वारा आगे केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाए।
- जिला स्तर पर यूरिया जैसे उर्वरकों का अतिरिक्त भंडार बनाने की संभावनाएँ तलाशी जानी चाहिये।
- राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चर्चा सत्र के दौरान कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से क्रेडिट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन, किसान कल्याण और उर्वरक जैसे विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।

देश की पहली 'ई-बीट बुक' और 'ई-साथी' ऐप ऐप की शुरुआत

PIB, (20 Sep, 2019)

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में देश की पहली एकीकृत ERSS, E-Beat Book, E-SAATHI App का लोकार्पण किया गया।
- इससे चण्डीगढ में आम नागरिकों को आपातकाल में सहायता के लिये अलग-अलग नम्बर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके लिए नयी सेवा एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 पर सभी तरह की सहायता आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड के अंतर्गत इस तरह के ऐप को जनता के लिए उपलब्ध कराया ताकि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों मे कमी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त ई-बीट बुक और ई-साथी ऐप भी आरंभ किये गये हैं।

ई-बीट बुक

- ई-बीट बुक सिस्टम के तहत हर "ई-बीट बुक" के ईचार्ज को एंडरॉयड फोन दिये गये हैं, जिसके अन्दर बीट-इंचार्ज के पास पुलिसिंग का पूरा रिकार्ड होगा तथा इस फोन पर एक क्लिक करते ही शहर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जैसे की बाजार, आभूषण विक्रेता, शराब के ठेके, वरिष्ठ नागरिकों की सूची, पीजी क्षेत्र के अच्छे बुरे नागरिकों के बारे में बीट ईचार्ज को मिल जायेंगी।

- ई-बीट बुक पर अपराधियों के बारे में पूरा रिकार्ड दर्ज होगा। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, नशा-बिक्री, जुआ-सट्टे बाजी आदि की जानकारी पुलिस को आसानी से दे सकेगा।
- इसके साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक भी इस ऐप के माध्यम से पुलिस के सम्पर्क में रहेंगे। ई-बीट मेन इंटरएक्टिव फीचर भी होगा जिससे की सम्बंधित क्षेत्र के निवासी सीधा सम्पर्क करके अपने सुझाव और शिकायत दे पायेंगे।

ई-साथी ऐप

- "ई-साथी ऐप" से आम जनता को बिना थाने में गए "आपकी पुलिस आपके द्वार" योजना के तहत पासपोर्ट सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, चरित्र सत्यापन आदि सेवाओं की अपने क्षेत्र के थाना-अध्यक्ष को सूचना देनी होगी और उनके एक बटन दबाते ही संबंधित थानाध्यक्ष उनके दिए हुए समय पर बीट सिपाही भेजकर वाँछित सेवा प्रदान करेगा।
- इसके लिये नागरिकों को एक बटन दबाकर संबंधित ऐप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा। इस प्रोद्योगिकी तकनीकी कुशलता से एक ओर जहां बीट सिपाही सशक्त और सक्षम होगा वहीं ये सीसीटीएनएस और ईआरएसएस से पूर्णत: समायोजित व अनुकूल होगा।

भारत 2022 तक गैर-जीवाश्म ईंधन में 175 गीगावॉट तक हिस्सा बढ़ाएगा: प्रधानमंत्री

PIB, (23 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) जलवायु कार्ययोजना शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2022 तक गैर-जीवाश्म ईंधन में 175 गीगावॉट तक हिस्सा बढ़ाएगा और तदुपरांत इस हिस्से को 450 गीगावॉट तक ले जाएगा।
- साथ ही उन्होंने कहा कि कहा, "हमारा मार्गदर्शन सिद्धांत हमेशा से आवश्यकता रहा है, न की लालसा।"

सम्मेलन के मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनों को ध्यान दिलाते हुए कहा, हमने जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण और जल स्रोतों के विकास के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। भारत अगले चंद वर्षों में इस मद में लगभग 50 अरब डॉलर खर्च करेगा।
- प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे को समाप्त करने के लिए जनांदोलन का आह्वान किया है।
- प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को आमंत्रित करते हुए कहा, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 80 देश हमारे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अभियान में शामिल हो चुके हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कई कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

चिह्नित प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं -

- **वित्त :** सभी प्राथमिकता वाले सेक्टरों में कार्बन की कमी लाने और उन्नत रोधी क्षमता के लिए सार्वजनिक तथा निजी वित्त स्रोतों को लामबंद करना।
- **ऊर्जा अंतरण :** जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेज कदम बढ़ाना तथा ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना।
- **उद्योग अंतरण :** तेल एवं गैस, इस्पात, सीमेंट, रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में परिवर्तन करना।
- **प्रकृतिक आधारित समाधान :** उत्सर्जन में कमी लाना तथा जैव विविधता संरक्षण, आपूर्ति श्रृंखला एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिये वन, कृषि, महासागर तथा खाद्य प्रणालियों में रोधी क्षमता बढ़ाना तथा पर्यावरण को अवांच्छित सहायक उत्पादों तथा खपत के दुष्प्रभावों को सहने योग्य बनाना।
- **शहर और स्थानीय कार्ययोजना :** शहरी और स्थानीय स्तर पर रोधी क्षमता बढ़ाना। इसके तहत कम उत्सर्जन वाली इमारतों, जनयातायात, शहरी अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाना। इसके अलावा शहरी गरीबों के अनुकूल कदम उठाना।
- **आपदारोधी उपाय अपनाना :** सबसे अधिक संवेदनशील समुदायों और देशों के मद्देनजर जलावायु परिवर्तन के जोखिमों और दुष्प्रभावों का हल निकालने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाना।
- **उपशमन रणनीति :** पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर महत्त्वाकांक्षी एनडीसी और दीर्घकालीन रणनीतियों में तेजी लाना।

- **युवाओं और जनता को लामबंद करना :** जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में दुनियाभर के लोगों को लामबंद करना तथा 6 परिवर्तनीय क्षेत्रों सहित शिखर सम्मेलन के सभी पहलुओं के संबंध में युवाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी : वायु प्रदूषण को कम करने, बेहतर रोजगारों के सृजन, जलवायु संबंधी रणनीतियों को मजबूत बनाने तथा कामगारों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रतिबद्धता जाहिर करना।

"उम्मीद" पहल का शुभारंभ

PIB, (23 Sep, 2019)

संदर्भ

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने UMMID - उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल का शुभारंभ किया तथा निदान (राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन) केंद्रों का उद्घाटन किया।
- इन केंद्रों की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

क्या है UMMID और NIDAN?

- डॉ. हर्षवर्धन ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए यह पहल आरंभ की गई है।
- UMMID के द्वारा नवजात शिशुओं के माता-पिता को जागरुक किया जायेगा और उन्हें अपने बच्चों को आनुवांशिक बीमारियों से बचाने के लिए बताया जायेगा।
- इसके साथ ही NIDAN केन्द्रों की स्थापना UMMID पहल के तहत की जाएगी। इन केंद्रों की स्थापना के लिए देश के 115 जिलों की पहचान की गई है। इन केंद्रों में परिजनों को काउंसलिंग, टेस्टिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

उद्देश्य

- इस अवसर पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि इस पहल से उन बच्चों की जान बचाई जा सकती है जो घातक आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं।
- साथ ही, इससे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।
- वर्ष 2022 तक 75 नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद और कोलकाता में इन केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है।
- दिल्ली स्थिति लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एयर फोर्स रिसर्च सेंटर में इन केंद्रों की स्थापना की गई है।

भारत और यूएई के बीच आबूधाबी में आयोजित 7वीं उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबल बैठक

PIB, (23 Sep, 2019)

संदर्भ

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच निवेश पर 7वीं उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबल बैठक 22 सितम्बर, 2019 को आबूधाबी में आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

इसका गठन क्यों हुआ?

- कार्य समूह का गठन भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- दोनों देशों ने जनवरी 2017 में शेख हामिद बिन जायेद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षर किये गये व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते को लागू किया है।
- दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने और आपसी चिंताओं को दूर करने के संदर्भ में कार्य समूह ने नया महत्व हासिल कर लिया है।

मुख्य बिंदु

- कार्य समूह की 7वीं बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परस्पर चिन्हित क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के सफल परिणामों को रेखांकित किया।
- दोनों पक्षों ने एडीआईए के पूर्ण स्वामित्व वाले आबूधाबी वैश्विक बाजार-एडीजीएम के संबंध में कर प्रावधानों के मुद्दे पर भी चर्चा की। भारत ने इस मुद्दे पर एडीआईए के लिए अपने यहां निवेश को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिये जाने का आश्वासन दिया।
- अपने देशों के व्यापारिक समुदायों का विश्वास बढ़ाने के लिए, दोनों पक्षों ने नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में अदालत के फैसले की मान्यता और प्रवर्तनीयता तथा मध्यस्थता के माध्यम से द्विपक्षीय न्यायिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
- बैठक में भारतीय बैंकों के विकास के अवसरों, एडीजीएम के परिसंपत्ति प्रबंधकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों और एडीजीएम

में अपनी सेवाएं देने वाले निजी बैंकों के लिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली निजी वित्त सेवाओं की पेशकश की संभावनाओं सहित भविष्य में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई।

- दोनों पक्षों ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात के निवेश से संबंधित मुद्दों को सुलझाने और निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए 6 एचएलटीएफआई में-यूएई प्लस 'विशेष डेस्क और फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म' के कामकाज की सराहना की।
- दोनों पक्षों ने 2012 में अपने कार्यबल के गठन के बाद से की गई कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रगति के क्षेत्रों की समीक्षा की और उनपर संतोष व्यक्त किया। इनमें निवेशों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए एक द्विपक्षीय समझौते, भारत के पेट्रोलियम रणनीतिक भंडार में यूएई के योगदान,भारत के अवसंरचना विकास कोष में पहले विदेशी संस्थागत निवेश के तौर पर एडीआईए की भागीदारी तथा भारतीय बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में यूएई की निवेशक ईकाईयों के लिए निवेश की सीमा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में तीन नए आयुष अस्पताल बनाए गए

PIB, (24 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद नाइक ने कहा है कि वर्तमान सरकार के 100 दिनों के अंदर राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में तीन नए आयुष अस्पतालों का निर्माण किया गया है और 306 आयुष अस्पतालों का उन्नयन किया गया है।
- 11,980 अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। इससे 2.9 करोड़ मरीजों को लाभ होगा।
- आयुष केंद्रों के निकट स्थित 2853 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दवाओं व अन्य सुविधाओं की समय-सीमा में विस्तार दिया गया है। इससे 64.6 लाख मरीज लाभान्वित होंगे।

मुख्य बिंदु

- 2019-20 के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत 4200 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- राज्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की जांच के बाद 1754 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा 1037 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को 325 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। औषधीय पौधों की खेती करने से संबंधित 17 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- 6500 हेक्टेयर क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये की लागत से औषधीय पौधों की खेती की जाएगी। इससे 3000 किसानों को लाभ मिलेगा।
- राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2019 से अगले एक साल तक 150 मेगा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

- बिम्सटेक के सदस्य देश भारत में बिम्सटेक आयुर्वेद और पारंपरिक औषधि विश्वविद्यालय की संयुक्त रूप से स्थापना करने पर सहमत हुए हैं।
- औषधि की पारंपरिक प्रणाली तथा होम्योपैथिक के क्षेत्र में भारत ने गाम्बिया और गिनी के साथ समझौते किए हैं। भारत और चीन ने 12 अगस्त, 2019 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
- अगले दो वर्षों के लिए आयुष प्रणाली में अनुसंधान के लिए 490 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) विषय पर आयुर्वेद हस्तक्षेप पर अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान कार्यक्रम में 10,000 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध अनुसंधान परिषदों ने 110 सूत्रीकरण तथा 60 रोग-स्थितियों की निदान संबंधी सुरक्षित होने की पुष्टि की है। मंत्रालय के अंतर्गत 10 राष्ट्रीय संस्थान नए कीर्तिमान बना रहे हैं।
- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के उन्नयन का कार्य जारी है और इसके दूसरे कैंपस के लिए 1.37 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

16वें ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट

PIB, (24 Sep, 2019)

संदर्भ

- हल ही में केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी ने नई दिल्ली में 16वें ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट 2019 का उद्घाटन किया।

- यह समिट हर साल एसएमई मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

- इस वर्ष के समिट का विषय है-'भारतीय एसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना'।

मुख्य बिंदु

- सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में जीडीपी में एसएमई की मौजूदा 29 प्रतिशत की भागीदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है तथा निर्यात में इसके योगदान को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना है।
- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स, बिजली और पूंजी की लागत में कमी लाने की आवश्यकता है।
- बिजली और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाने के लिए ऊर्जा ऑडिट और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर बल दिया।
- केएफडब्ल्यू के सहयोग से एसएमई को रूफ टॉप सोलर प्लांट मुहैया किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल परिवहन के उपयोग से लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत में कमी लाई जा सकती है।
- एसएमई को अपने उत्पाद स्थानीय साथ-ही-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने में समर्थ बनाने के लिए उनका मंत्रालय जल्द ही ई-कॉमर्स वेबसाइट 'भारत मार्ट' का शुभारंभ करेगा।
- उद्यमी के कौशल का विकास करने के लिए 135 नए टूल रूम्स और प्रौद्योगिकी केन्द्र खोले जा रहे हैं।
- इस समिट में 15 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब के साथ कंट्री सेशन्स के अलावा 'क्या एमएसएमई भारत के जीडीपी में 50 प्रतिशत योगदान दे सकता है?' विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।
- समिट के दूसरे दिन कल कंट्री सेशन्स, रीजनल सेशन्स और बी2बी बैठकों के अलावा ई-कॉमर्स डिजिटलीकरण पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

आईसीजीएस 'वराह' का जलावतरण

PIB, (25 Sep, 2019)

संदर्भ

- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2019 को यहां चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में औपचारिक रूप से तटरक्षक बल के तटीय गश्ती जहाज 'वराह' का जलावतरण किया।
- यह विशेष अत्याधुनिक जहाज भारतीय तटरक्षक बल की ताकत में और इजाफा करेगा।
- इस जहाज में स्वदेशी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित दोहरे इंजन वाले एएलएच हेलीकॉप्टरों के संचालन की क्षमता है।
- श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के सरकारी विजन पर अमल करते हुए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में 'भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015-2030' तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज का उद्देश्य अगले 15 वर्षों के दौरान विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों का स्वदेशी विकास सुनिश्चित करना है।

वराह' नाम पुराणों से लिया गया

- रक्षा मंत्री ने कहा कि 'वराह' नाम पुराणों से लिया गया है। यह नाम त्याग और समुद्र में बचाव और सौहार्द्र एवं ताकत बनाये रखने के सिद्धांत की याद दिलाता है।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी तथा समुद्री

आतंकवाद के बढ़ते खतरे ने बहुत साल से विभिन्न समुद्री देशों एवं भारतीय तट रक्षक की क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर सहायता की दिशा में आह्वान किया है।

जहाज की विशेषता

- इस जहाज में एडवांस्ड नेविगेशन तथा संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी का प्रयोग किया गया है। इसमें एक 30 मिमी तथा दो 12.7 मिमी बंदूक (गन) का प्रयोग किया गया है। इसकी अधिकतम गति 26 नॉट है।
- इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ऑटोमेटेड पॉवर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट हाई पॉवर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है।
- इसका संचालन विशिष्ट आर्थिक जोन से लेकर कन्याकुमारी तक को कवर करने वाले पश्चिमी तट पर स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाएगा।
- आईसीजीएस 'वराह' हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा स्वदेश में विकसित उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर का संचालन करने में सक्षम है।
- यह पोत अत्यंत तेज गति से चलने वाली नौकाओं, चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक निगरानी प्रणालियों से लैस है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तटरक्षक बल ने समुद्री खतरों से निपटने हेतु क्षमता निर्माण, समेकित प्रशिक्षण एवं सहयोग हेतु सात समुद्री देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।

केंद्र सरकार ने शुरू किया सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार

PIB, (25 Sep, 2019)

संदर्भ

- हल ही में केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान हेतु सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है।
- गृह मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की एक अधिसूचना जारी की गई थी।
- इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत और अखण्ड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है।

पुरस्कार की घोषणा

- इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर की जाएगी।
- यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक सनद के तौर पर प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में उनके द्वारा दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पुरस्कार में एक पदक तथा एक प्रशस्ति पत्र होगा। यह सम्मान विशेष स्थिति तथा अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।
- इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक राशि या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। तीन से अधिक पुरस्कार एक साल में नहीं दिए जाएंगे।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक भारत में स्थित संस्था या संगठन या कोई भी भारतीय नागरिक इस पुरस्कार हेतु विचारार्थ किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है।
- इस पुरस्कार के लिए राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं। नामांकन प्रति वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे।
- आवेदनों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की बनावट कमल की पत्ती की तरह होगी।

पुरस्कार समिति का गठन

- प्रधानमंत्री द्वारा एक पुरस्कार समिति का गठन किया जाएगा।
- इस समिति में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव सदस्य होंगे।
- इसके अतिरिक्त इस समिति में प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए तीन-चार गणमान्य लोग भी शामिल होंगे।

मालाबार 2019 अभ्यास

PIB, (25 Sep, 2019)

संदर्भ

- भारत, जापान और अमरीका की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्रीय अभ्यास मालाबार के 23वें संस्करण का आयोजन 26 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक जापान के तट के समीप किया गया।
- इस अभ्यास में भाग लेने के लिए स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित किये गए भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन पोत, बहु-उद्देश्यीय निर्देशित मिसाइल युद्धपोत सहयाद्री तथा एएसडब्ल्यू कॉर्वेट किलतान पर सवार होकर रियर एडमिरल सूरज बैरी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी बेड़ा, आज सुबह सासेबो पहुंचे।

- युद्धपोतों के अलावा लंबी दूरी का सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान 'पी81' भी इस अभ्यास के लिए जापान पहुंचा है।
- अमरीकी नौसेना का प्रतिनिधित्व लॉस एंजेलिस-क्लास अटैक सबमरीन यूएसएस मैककैम्बेल और लंबी दूरी के सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान 'पी8ए' कर रहे हैं।
- जेएमएसडीएफ अपने इजुमो क्लास हेलिकॉप्टर डेस्ट्रॉयर जेएस

कागा, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जेएस सामीदारे और छोकाई तथा लंबी दूरी का सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान 'पी1' के साथ भाग ले रही है।

मुख्य बिंदु

- मालाबार 2019 भारत-जापान-अमरीका नौसेना सहयोग को और मजबूती प्रदान करेगा तथा साझा मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित पारस्परिकता में वृद्धि करेगा।
- इस अभ्यास में सतह, उप-सतह और वायु क्षेत्रों में जटिल सामुद्रिक ऑपरेशन शामिल होंगे तथा पनडुब्बी-रोधी युद्ध, विमान-रोधी और पनडुब्बी-रोधी फायरिंग, मैरीटाइम इन्टर्डिक्शन ऑपरेशन्स (एमआईओ) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अभ्यास में भारतीय नौसेना के पोत और लड़ाकू विमान तीनों देशों के बीच सामुद्रिक संबंधों को महत्त्वपूर्ण रूप से मजबूती प्रदान करेंगे और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व में योगदान देंगे।

थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष

PIB, (27 Sep, 2019)

सन्दर्भ

- थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले यह पद वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ के पास था। सीओएससी तीनों सेनाध्यक्षों को मिलकर बनी हुई एक कमेटी है।
- हमेशा इसका अध्यक्ष तीनों सेनाध्यक्षों में जो सबसे वरिष्ठ होता

है उसके पास होता है। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ इस महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। जिसके बाद वरिष्ठता की सूची में थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का स्थान है।

- जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर, 2016 को सेना प्रमुख पद संभाला था। बता दें कि एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने 29 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से सीओएससी अध्यक्ष का प्रभार लिया था।

चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी)

- चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के पास तीन सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने तथा देश के सामने मौजूद बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु सामान्य रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी होती है।
- सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख सीओएससी में शामिल हैं। तीनों सेनाओं में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सीओएससी के चेयरमैन के पास तीन सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है।
- सीओएससी के पास देश के सामने मौजूद बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु सामान्य रणनीति तैयार करने का दायित्व भी होता है। यह एक ऐसी एजेंसी है, जिसका काम भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल स्थापित करना है।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि अब देश के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद होगा।
- इस समय रक्षा मंत्रालय विभिन्न तौर-तरीकों और प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत इस पद को सीडीएस में बदल दिया जाएगा।
- यदि इस साल खत्म होने से पहले सीडीएस का गठन हो जाता है तो जनरल रावत अंतिम व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें सीओएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है क्योंकि सीडीएस के गठन के बाद सीओएससी अध्यक्ष का पद खत्म कर दिया जाएगा।

आईएनएस खंडेरी

PIB, (28 Sep, 2019)

सन्दर्भ

- हाल ही में 28 सितंबर, 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया।
- आईएनएस खंडेरी भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों में दूसरी पनडुब्बी है।
- इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।

मुख्य बिंदु

- यह पनडुब्बी भारत में फ्रांसीसी स्कॉर्पियन डिजाइन से प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित दूसरी पनडुब्बी है।
- आईएनएस कलवरी, फ्रांसीसी मूल की भारत में निर्मित स्कॉर्पियन

क्लास की पहली पनडुब्बी थी।

- आईएनएस खंडेरी को 19 सितंबर, 2019 को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया था।
- इस पनडुब्बी का नाम महान मसठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा बनवाए गए द्वीपीय किले खंडेरी के नाम पर रखा गया है।
- मध्यकालीन युग में शिवाजी पहले भारतीय शासक थे, जिन्होंने नौसेना की महत्ता को समझा।
- इसके अलावा खंडेरी नाम समुद्र के अधोभाग के निकट तैरते हुए शिकार के लिए जानी जाने वाली घातक 'सोर्ड टूथ मछली' से भी प्रेरित है।

विशेषता

- आईएनएस खंडेरी की मुख्य विशेषता है कि यह किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी।
- यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, इस पर टॉरपीडो तथा एंटीशिप मिसाइल तैनात की जाएंगी।
- यह पनडुब्बी पानी से पानी में किसी पनडुब्बी को और पानी से किसी भी युद्धपोत को ध्वस्त करने में सक्षम है।
- यह पनडुबी 1 घंटे में 35 किमी. की दूरी तय कर सकती है और सागर में 350 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है।
- यह 67.5 मीटर लंबी, 6.2 मीटर चौड़ी और 12.3 मीटर ऊंची है।
- इसका कुल वजन 1550 टन है।
- यह पनडुब्बी पानी में एक बार में 12000 किमी. का सफर तय कर सकती है।
- आईएनएस खंडेरी की अधिकतम गति 20 समुद्री मील प्रति घंटा है।

नीति आयोग ने स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) जारी किया

PIB, (30 Sep, 2019)

संदर्भ

- हाल ही में नीति आयोग ने 30 सितंबर 2019 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआइ) जारी किया है।
- इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है. इस सूची में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है।
- नीति आयोग की ओर से जारी इस सूची में देश के 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है।

- द सक्से ऑफ आवर स्कूल्स-स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (एसईक्यूआई) में 2016-17 का संदर्भ वर्ष और 2015-16 का आधार वर्ष के रूप में इस्तेमाल किया है। एसईक्यूआई को स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है।

- सूचकांक छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रयासों पर जोर देता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर सूची में 18वें और 19वें स्थान पर हैं।
- इस रिपोर्ट को नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से जारी किया है।

सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघशासित प्रदेश

- **बड़े राज्य**- केरल, राजस्थान, कर्नाटक
- **छोटे राज्य**- मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा
- **केंद्र शासित प्रदेश**- चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली

मुख्य बिंदु

- सूची को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है - बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
- शीर्ष तीन राज्यों में केरल, राजस्थान और कर्नाटक हैं और, तीन निचले राज्यों में पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश हैं।
- जिन छोटे राज्यों को अलग से जगह दिया गया है। उनमें आठ राज्य शामिल हैं - मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश।
- उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रदर्शन खराब है।

जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी बैठक

PIB, (30 Sep, 2019)

सन्दर्भ

- भारत 30 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी) कार्य समूह III की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट पर अंतर सरकारी पैनल के प्रमुख लेखकों की दूसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है।
- नई दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाली इस बैठक में 200 से अधिक विशेषज्ञ/लेखकों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भारत के 12 विशेषज्ञ / लेखक और अन्य लगभग 65 देशों से हैं।

- कार्य समूह III के सह अध्यक्ष श्री जिम स्केया ने छठी मूल्यांकन रिपोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा पिछले कार्य समूह III के आकलन की रचना पर, यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देगी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए निकट भविष्य में क्या किया जा सकता है, और इस प्रकार नीतिगत, संस्थागत निर्माण और निधियन के जरिए इसे कैसे कम किया जा सकता है।

कार्य

- छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर-6) उपभोग और आचरण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच की कड़ी और नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों की जांच करेगी।
- रिपोर्ट मध्यम-अवधि के कार्यों के बीच संबंध और पेरिस समझौते में दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य के साथ उनकी संगतता का आकलन करेगी। यह ऊर्जा, कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग, भवन, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में शमन विकल्पों का आकलन करेगी।
- पहले आदेश का मसौदा 13 जनवरी से 8 मार्च, 2020 तक विशेषज्ञ समीक्षा के लिए उपलब्ध होगा। आदेश का दूसरा मसौदा सरकार और विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए 13 जुलाई से 13 सितंबर 2020 तक खुला रहेगा, साथ ही नीति निर्माताओं के लिए संक्षिप्त विवरण का पहला मसौदा उपलब्ध होगा।
- आईपीसीसी पैनल 12 से 16 जुलाई 2021 को एक पूर्ण सत्र में आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट में कार्य समूह III के योगदान पर विचार करेगा।
- आईपीसीसी के तीन कार्य समूहों में से प्रत्येक 2021 में छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में अपना योगदान जारी करेगा। 2022 में एक संश्लेषण रिपोर्ट उन्हें तीन विशेष रिपोर्टों के साथ जोड़ेगी

आईपीसीसी के बारे में

- आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का संगठन है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा 1988 में की गई थी।

GS World Committed To Excellence

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. अंगीकार अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसमें पीएमएवाईयू यू के बनाये गए घरों के लाभार्थियों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई जैसे मुद्दों पर सामुदायिक जुटाव और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है।
2. सभी लक्षित शहरों में यह अभियान प्रारंभिक चरण के बाद महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू होगा और 10 दिसम्बर, 2019 को मानवाधिकार के अवसर पर इसका समापन किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. अतिसंवेदनशीलता एटलस पर सरकार द्वारा शुरू की गई ई-कोर्स पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) नई दिल्ली तथा भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौधोगिकी संवर्द्धन परिषद (BMTPC) की संयुक्त पहल है।
2. इसमें प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरूकता एवं समझ प्रदान करने के साथ वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग शहरी एवं क्षेत्रीय योजना आदि के लिए एक प्रभावी व कुशल साधन हो सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के मेगा मिलियन लांच के अवसर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) और मतदाता हेल्पलाईन ऐप (VHA) संबंधित निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए-

1. इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को बेहतर बनाना एवं आयोग तथा मतदाताओं के बीच संवाद को बेहतर बनाना है।
2. यह कार्यक्रम 1 सितंबर, 2019 से 20 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा।
3. मतदाता सूची की क्रमसंख्या में बदलाव, मतदाताओं केंद्र का ब्यौरा बीएल ओ/ ई आर ओ में बदलाव संबंधित मतदान केन्द्र की सभी जानकारी मादाताओं के साथ साझा की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. भारत को चीन से दो वर्षों के लिए सीओपी की अध्यक्षता प्रदान की गई है। सीओपी के मुख्य बिंदुओं पर विचार कीजिए-

1. सम्मेलन में 195 दलों के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों, वैश्विक व्यापार नेताओं सामुदायिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
2. सीओपी 14 के प्रमुख परिणाम कृषि, वानिकी, भूमि, जल प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में मौजूदा कार्यक्रमों के बीच अभिसरण और समन्वय करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. हाल ही में टेराकोटा ग्राइंडर लांच किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी की सेवापुरी में टेरोकोटा ग्राइंडर लांच किया।
2. ग्रामीणों के बीच 200 इलेक्ट्रिक पॉवर व्हील्स और अन्य पॉटरी मशीनों का वितरण किया गया, इससे 900 नए रोजगार सृजित होंगे।
3. रेलवे मंत्रालय द्वारा जोनल रेलवे और आई.आर.सी.टी.सी. निर्देशानुसार वाराणसी रेलवे स्टेशन पर टेराकोटा उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. री प्लान परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्वच्छ भारत अभियान के तहत जयपुर में प्लास्टिक मिश्रित कागज का निर्माण प्रारंभ किया गया।

2. यह निर्माण कार्य री प्लान परियोजना के तहत किया गया है।
3. कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान द्वारा सितंबर, 2018 तक छः लाख से अधिक हस्तनिर्मित प्लास्टिक मिश्रित कैरी बैग बेचे गये हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

7. लुईस मैक कॉर्डवाशिंगटन में संपन्न भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित किए जाने वाले युद्ध अभ्यास का यह 14वां संस्करण है।
2. यह युद्ध अभ्यास एक दूसरे की विशेषज्ञता तथा नियोजन और संचालन क्रियान्वयन के अनुभव को सीखने का आदर्शमंच है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. भारत और रूस के बीच 2019 में हुए हाइड्रोकार्बन समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस समझौते की अवधि 2019-24 है।
2. इस समझौते से रूस अपने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को भारत की गैस परियोजनाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा।
3. दोनों पक्षों में ऊर्जा क्षेत्र के साथ संयुक्त अनुसंधान के नये तरीके विकसित करने पर भी विचार किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. हाल ही में छठी भारत चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता (SED) संपन्न हुई है। एसईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एसईडी का गठन दिसंबर, 2011 में किया गया।
2. 5वीं एसईडी का आयोजन, 2018 में बीजिंग में हुआ था।
3. भारतीय पक्ष का नेतृत्व नीति आयोग के चेयरमैन करेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. सितंबर, 2019 में आयोजित 28वां भारत थाईलैंड कॉरपेट से संबंतिध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 2003 से ही हर दो वर्ष के अंतराल में एक बार थाईलैंड की शाही सेना और अंडमान निकोबार कमान के भारतीय नौ सेना के पोत और हवाई जाहज इस कारपेट में हिस्सा लेते रहे हैं।
2. 28वीं इंडोथाई कारपेट से भारत और थाइलैंड के बीच समुद्री सहयोग बढ़ेगा और अरब सागर में शांति व्यवस्था बनेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

11. 14वें मरूस्थलीकरण रोकथाम (2019) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कॉप 14) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस बार का सम्मेलन भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित हुआ।
2. भारत ने 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर से 26 मिलियन हेक्टेयर तक की डीग्रेडेड भूमि को ठीक करने की महत्त्वाकांक्षा रखी है।
3. फ्रांस की तरफ से यूएनसीसीडी के सदस्य देशों की क्षमता निर्माण तथा समर्थन के लिए एक वैश्विक संस्थान बनाने का पक्ष रखा गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन असत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

12. सितंबर, 2019 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन की शुरूआत की गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह सम्मेलन भारत और रूस के सहयोग से सम्पन्न किया गया।
2. यह सम्मेलन संसाधनों की दक्षता पर विचार विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

13. मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन से संबंधित कौन-सा कथन असत्य है?

(a) दक्षिण एशिया की दूसरी सीमा पार जाने वाली पाइपलाइन है।
(b) 69 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी।
(c) इस पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।
(d) इस पाइपलाइन से नेपाल के पेट्रोलियम उत्पाद के दामों में कटौती होगी।

14. हाल ही में भारत का सबसे ऊँचा हवाई यातायात नियंत्रण टॉवर बनाया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस टॉवर का निर्माण राजीव गाँधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया है।
2. यहाँ से हवाई यातायात नियंत्रक एयरपोर्ट के रनवे, टैक्सी वे, पार्किंग स्टैंड सहित तमाम परिचालन गतिविधियां देखी जा सकेंगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

15. स्वच्छता ही सेवा-2019 अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अभियान की शुरूआत नई दिल्ली से की गई।
2. प्लास्टिक कचरा जागरूकता और प्रबंधन पर जोर दिया गया है।
3. 2 अक्टूबर, 2019 को ही राष्ट्रव्यापी श्रमदान के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

16. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इस योजना का शुभारंभ झारखण्ड के रांची में किया गया।
2. इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को 65 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3500 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी।
3. यह केन्द्र सरकार के द्वारा वित्तपोषित एवं स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

17. हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह पेंशन योजना दुकानदारों खुदरा व्यापारियों तथा स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है।
2. 30 लाख से अधिक वार्षिक व्यापार वाले व्यापारियों के लिए जी.एस.टी.आई.एन. की जरूरत है।
3. इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% और शेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

18. हाल ही में भारत ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एण्ड डेवलमेंट (AMRR&D) हब में शामिल हो गया है। AMRR&D के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. G-20 नेताओं द्वारा इस हब की शुरूआत मई 2018 में की गई थी।
2. इस हब से भारत दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने में समक्ष होगा।
3. ग्लोबल एएमआरआरएंडडी हब का परिचालन जेनेवा स्थित सचिवालय से हो रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

19. हाल ही में इस्पात आयात प्रणाली लॉन्च किया गया है। इसके संदर्भ में दिये गये निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कीजिए-

1. इस्पात आयात प्रणाली को 5 सितम्बर 2019 को अधिसूचना संख्या 17 के जरिए अधिसूचित किया गया है।
2. यह पंजीकरण माल आगमन के 60 वें दिन से पहले और 15वें दिन के बाद नहीं किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

20. विश्व ओजोन दिवस 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस वर्ष की थीम-32 Years and Healing है।
2. भारत मार्च 2019 में समग्र कूलिंग एक्शन प्लान शुरू करने वाले देशों में शामिल हो गया है।
3. आजोन गैस का निर्माण केवल प्राकृति रूप से होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

21. हाल ही में अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र के संदर्भ में दिए गये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
2. इस मिसाइल में द्रव ईंधन प्रणोदक का प्रयोग किया गया है।
3. इस मिसाइल को डी.आर.डी.ओ. ने मिराज-2000 और सुखोई एस.यू.-30 एम के आई विमानों में लगाने हेतु विकसित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य नहीं हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

22. हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कीजिए-

1. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के भंडारण के लिए भी 6 माह तक कैद अथवा 50 हजार रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।
2. पुलिस निरीक्षक को अध्यादेश के तहत कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

23. राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रवि अभियान 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. कृषि विभाग ने राज्यों के कृषि विभागों की सक्रिय भागीदारी से बीज के मिनी किट वितरित करने का निर्णय लिया है।
2. तिलहन और दहलन की 45 जैव बायोफोर्टिफिकेशन किस्में जारी की गई हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

24. देश की पहली ई बीट बुक और ई-साथी ऐप की शुरूआत की गई है। बीट बुक और ई-साथी ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. ई बुक बीट सिस्टम के तहत शहर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ बीट ईंचार्ज को मिल जायेगी।
2. ई-साथी ऐप से आम जनता को बिना थाने गए आपकी पुलिस आपके द्वारा योजना के तहत वांछित सेवा प्रदान किया जायेगा।
3. ये दोनों कार्यक्रम उत्तर-प्रदेश में आम नागरिकों को आपातकाल में सहायता के लिए प्रारंभ किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

25. गैर जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को किस वर्ष तक 175 गीगावॉट तक बढ़ाया जाना निर्धारित किया गया है?

(a) 2022 (b) 2023
(c) 2024 (d) 2025

26. उम्मीद पहल और निदान केन्द्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस पहल की शुरूआत की गई है।
2. 115 जिलों की पहचान की गई है जहां परिजनों को काउंसलिंग टेस्टिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए निदान केन्द्र खोले जायेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c)1 और 2 दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

27. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सम्पन्न 7वीं उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबल बैठक सितम्बर में आयोजित की गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया।
2. इस बैठक का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

28. आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित कार्यक्रमों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राजस्थान, झारखण्ड, ओड़िशा में तीन नए आयुष अस्पताल बनाए जा रहे हैं।
2. राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2019 से अगले एक साल तक 150 मेगा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर आयोजित किये जाएंगे।
3. आसियान के सदस्य देश भारत में आसियान आयुर्वेद और पारंपरिक औषधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर सहमत हुए हैं?

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

29. 16वें ग्लोबल एम.एस.एम.ई. बिजनेस समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. वर्ष 2019 के समिट का विषय है- भारतीय एम.एम. एम.एस. ई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
2. उद्यमी के कौशल का विकास करने के लिए 135 नए टूल रूम्स प्रौद्योगिकी केन्द्र खोले जा रहे हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

30. तटीय गश्ती जहाज 'वराह' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह पोत अत्यंत तेज गति से चलने वाली नौकाओं चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक निगरानी प्रणालियों से लैस है।
2. इसमें 12.7 मिमी बंदूक का प्रयोग किया गया है एवं इसकी अधिकतम गति 26 नॉट है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

31. केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखण्डता के क्षेत्र में योगदान हेतु सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है। इस सम्मान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह सम्मान विशेष स्थिति तथा अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाएगा।
2. चार से अधिक पुरस्कार एक साल में नहीं दिए जाएंगे।
3. पुरस्कार समिति में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव सदस्य होंगे।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के पास तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है।
2. सी.डी.एस. का गठन हो जाता है तो जनरल रावत अंतिम व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें सी.ओ.एस.सी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

33. आई.एन.एस खंडेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह पनडुब्बी भारत में रूसी स्कार्पियन डिजाइन से प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित दूसरी पनडुब्बी है।
2. इसकी मुख्य विशेषता है कि यह किसी रडार की पकड़ में नहीं आयेगी।
3. यह एक बार में 12000 किमी का सफर तय कर सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

34. नीति आयोग के द्वारा जारी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह रिपोर्ट नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से जारी किया है।
2. इसमें राजस्थान को दूसरा और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।
3. सूचकांक छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रयासों पर जोर देता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

35. जलवायु परिवर्तन (आई.पी.सी.सी.) 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. भारत आई.पी.सी.सी कार्य समूह III की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट पर अंतर सरकारी पैनल के प्रमुख लेखकों की दूसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है।
2. आई.पी.सी.सी. के तीन कार्य समूहों में से प्रत्येक 2021 में छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में अपना योगदान जारी करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

GS World Committed To Excellence